साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 30 | (प्रति बुधवार), इन्दौर, 15 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 | पेज : 8 | कीमत : 3 रुपये

प्लास्टिक संधि पर बंटी हुई है दुनिया, तेल उद्योग बन रहा बाधा

नई दिल्ली।

आगामी मई में पेरिस में प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर होने हैं, पर उससे पहले दुनिया के देश इस बात पर बंटे हैं कि क्या उत्पादित प्लास्टिक की मात्रा में कमी की जाए या केवल रीसाइक्लिंग के माध्यम से इसे जमीन और समुद्र को प्रदूषित करने से रोका जाए। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का तरीका क्या हो? एक तरफ प्लास्टिक को हतोत्साहित करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए घातक है, तो दूसरी तरफ तेल उद्योग अब भी इसके उत्पादन पर दांव लगा रहा है। प्लास्टिक उद्योग में तेल की बहुत खपत होती है, इसलिए तेल उद्योग का प्लास्टिक के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बढ़ गया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर सेकंड 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं, वहीं हर साल 260 से 270 खरब प्लास्टिक बैगों की खपत होती है।

प्लास्टिक उत्पादन से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम हानिकारक गैसों से उत्सर्जन और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी लागत और बायो डीग्रेडेबिल नहीं होने की वजह से इसके संग्रह की लागत और जमीन व समुद्र में इसका कूड़ा जमा होने से यह सभी के लिए एक मुसीबत बन चुका है। क्या जानवर और क्या इंसान, दोनों ही इसके कभी खत्म न होने वाले कचरे से बेहाल हैं। मई में प्लास्टिक संधि के लिए यूरोपीय संघ की पेशकश के हिसाब से, मांग कम करने से प्लास्टिक के उत्पादन स्तर में कमी की उम्मीद है। ब्रिटेन ने दुनिया के सभी देशों से प्लास्टिक उत्पादन और खपत को नियंत्रित करके कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों को अपनाने का आह्वान किया है। जबकि अफ्रीकी देशों के समूह ने प्लास्टिक उत्पादन को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा है।

अमेरिका और सऊदी अरब जैसे प्रमुख तेल और गैस उत्पादकों ने प्लास्टिक उत्पादन में कटौती का आह्वान नहीं किया। वे रीसाइक्लिंग और कचरे को कम करने के जरिये प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दरअसल, प्लास्टिक का उत्पादन तेल के उत्पादन पर निर्भर करता है। मतलब प्लास्टिक की मांग बढ़ेगी, तो तेल का उत्पादन भी उसी क्रम में बढ़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक उत्पादक देश चीन ने अपनी प्रस्तुति में कहा- प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए एक इंटीग्रेटेड आर्थिक और बाजारू तरीका अपनाना चाहिए।

गौरतलब है कि नैरोबी में 28 फरवरी, 2022 से दो मार्च, 2022 तक आयोजित पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के फिर से शुरू होने वाले सत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तीन मसौदा प्रस्तावों पर विचार किया गया था। भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव में देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई का आह्वान किया गया। दो मार्च, 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 2024 तक एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी मसौदा (संधि) तैयार करने के पक्ष में फैसला किया। भारत के आग्रह पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कार्रवाई करते समय राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमता के सिद्धांत को संकल्प के पाठ में शामिल किया गया, ताकि विकासशील देशों को उनके विकास पथ का अनुसरण करने की अनुमति मिल सके। यह संधि (प्लास्टिक ट्रीटि) 2024 में क्रियान्वित होगी। इसी की तैयारियों के लिए मई में दुनिया के सभी देश बैठक कर रहे हैं। भारत में हर साल 95 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। भारत ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। लेकिन यह लक्ष्य अभी हासिल नहीं हो पाया है। देश को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने का सफर आसान नहीं है और यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रतिबंध को कामयाब बनाने के लिए कंपनियों, केंद्र और राज्य सरकारों समेत उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका निभानी होगी। देशवासियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना होगा।

पर्यावरण बचाने की पहल, आज से हिमाचल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड खरीदेगा ई-कचरा

शिमला। ई-कचरा को लोग खुले में फेंक देते हैं या नदी नालों में फेंक देते है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड लोगों से ई-कचरा खरीदने की पहल शुरू कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घर में ई-कचरा पड़ा हुआ है उनको अच्छी कमाई हो सकती है, दरअसल हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आज से राज्य के लोगों से उनके घर में पडा ई कचरा खरीदना शुरू करेगा। इसके लिए बोर्ड राज्य में ई-कचरा कलेक्शन अभियान शुरू करने जा रहा है। ई-कचरा को लोग खुले में फेंक देते हैं या नदी नालों में फेंक देते है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड लोगों से ई-कचरा खरीदने की पहल शुरू कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घर में ई-कचरा पड़ा हुआ है उनको अच्छी कमाई हो सकती है, दरअसल हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आज से राज्य के लोगों से उनके घर में पडा ई कचरा खरीदना शुरू करेगा। इसके लिए बोर्ड राज्य में ई-कचरा कलेक्शन अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार लोगों से ई-कचरा लेगी और बदले में लोगों को पैसे मिलेंगे। ई-कचरा कलेक्शन के लिए सचिवालय में सेंटर खोला जा रहा है, जहां पर ई-कचरा जमा किया जाएगा। ई कचरा के तहत बोर्ड लोगों से बेकार पड़े मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, चार्जर केबल, प्रिंटर,सर्वर मॉडम, सीपीयू, माउस, की-बोर्ड, कंप्यूटर और उसके पार्ट सीपीयू,फ्रिज, वाशिंग मशीन, समेत बेकार हो चुके 124 प्रकार के इलेक्ट्रानिक सामान ख़रीदेगी। बोर्ड इलेक्टानिक कचरे को एम इलेक्ट्रानिक बोर्ड के माध्यम से 16 से 25 मार्च तक इकठ्ठा करेगा। ई कचरा को इकट्ठा करके नालागढ़ और बद्दी री-साइकिल प्लांट में भेजा जाएगा। प्रदेश में अभी लोग ई-वेस्ट को या तो खुले में डिस्पोज कर रहे हैं या उसे नदी नालों में फेंक कर ठिकाने लगा रहे हैं। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसे रोकने के लिए बोर्ड ने यह कदम उठाया है।

पर्यावरण संरक्षण का ऐसा जुनून कि मानसिंह 12 सालों से फ्री बांट रहे फलदार पौधे

दमोह जिले में एक ऐसे किसान हैं जो पर्यावरण संरक्षण को ही अपने जीने का मकसद मानते हैं. वह पिछले 12 वर्षों से लगातार अपनी मेहनत से पर्यावरण संरक्षण के काम मे जुटे हुए हैं. मानसिंह यादव की कड़ी मेहनत और परिश्रम अब रंग ला रही है. बता दें कि शासन द्वारा नौरादेही अभ्यारण्य में वन्य जीवों को बसाने के लिए उचित मुआवजा देकर आसपास के गांवों से ग्रामीणों को विस्थापित कर दिया गया था. इसे देख मानसिंह यादव ने भी पर्यावरण का महत्व जाना और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया.

मानसिंह यादव दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा तहसील से 50 किलोमीटर दूर सर्रा ग्राम के लगरा के निवासी हैं. उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा और जैविक खेती के लिए ग्रामीण इलाके में जागरूकता पैदा कर फलदार वृक्ष लगाने की शुरुआत की. इतना ही नहीं फलदार पौधे लगाने का शौक ऐसा कि कुछ बाजारों से तो कुछ पेड़ों के नीचे से बीज इकट्ठा कर अच्छे किस्म के बागवानी पौधों को तैयार कर किसानों को बांट दिए. यह काम वह बीते 12 वर्षों से करते आ रहे हैं, जिससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है.

अब जैविक खेती ही एममात्र उपाय मानसिंह यादव बताते हैं कि इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि आजकल फसलों की ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रासायनिक खादों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे फसलों की अच्छी पैदावार बढ़ाने में सफलता तो जरूर मिली लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार घट रही है. इसलिए अब जैविक खेती ही एक मात्र विकल्प है, जिससे केमिकल रहित फसल और धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है.

फल देने लगे वृक्ष मानसिंह यादव ने अब तक नए पर्यावरण को बचाने और ग्रामीणों को बागवानी खेती से जोड़ने के लिए 400 से अधिक फलदार वृक्षों को तैयार कर नि:शुल्क किसानों को वितरित किया है. इसमें से 250 से 300 के आसपास पौधे पनपकर फल भी देने लग गए हैं. जिनमें केला, अंगूर, मोसम्मी, नींबू, आम, नीम, आंवला, अमरूद के वृक्षों ने फल देना शुरू भी कर दिया है.

बाड़मेर में पर्यावरण बचाव की सराहनीय पहल, 101 वृक्ष रोप कर लोगों को किया जागरूक

बाड़मेर श्री रावल मल्लीनाथ, श्री राणी रूपादे संस्थान की ओर से मंगलवार को तिलवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विध्यालय मे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें विभिन्न प्रजाति के वृक्ष जैसे गुलमोहर, करंज, नीम, रोहिड़ा, पापड़ी, मोगरा, कनेर, बोगनवेल, टिकोमा, अरडू, जाल, खेजड़ी, नीरकुटी, चम्पा, सहजनार, गुलतारा इत्यादि 101 वृक्ष रोपे गए. प्रधानाचार्य जेठूसिंह द्वारा रावल साहब का स्वागत किया गया. साथ ही अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जेतमालसिंह द्वारा रावल किशनसिंह को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि रावल साहब की शिक्षा व पर्यावरण के प्रति जो पहल है उसकी मैं और पूरा शिक्षा विभाग सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विध्यालय रेबारियों कि ढाणी जो पिछले कई वर्षों से बिजली से वंचित थी उसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा जो सहायता की गई है उसके लिए विध्यालय हमेशा आभारी रहेगा. इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष रावल किशनसिंह ने कहा कि संस्थान सामाजिक सरोकार के तहत वर्ष भर मे कई कार्यक्रम आयोजित करता है. आज इसी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. वृक्षों के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए रावल किशनसिंह ने बताया कि हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. वृक्षों से हमे नई ऊर्जा का संचार होता है. इसलिए हमें समय-समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए तथा समय-समय पर इनकी देखभाल करते रहना चाहिए. श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान अध्यक्ष रावल किशनसिंह द्वारा इसी कार्यक्रम मे राजकीय उच्च प्राथमिक विध्यालय रेबारियों की ढाणी (सिनली जागीर) को आए बिजली के कनेकशन हेतु आवेदन के तहत डिमांड नोटिस 25647 रुपये राशि के चेक को स्कूल प्रधानाध्यापक राकेश रमन को सुपुर्द किया गया. इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जेतमालसिंह, प्रधानाचार्य जेठुसिंह, कुँवर हरिश्चंद्रसिंह जसोल, अध्यापक भंवरलाल, कुंदनसिंह, गणपतसिंह सिमालिया, बलवंतसिंह, जोगाराम देवासी वार्डपंच, तुलसाराम, हरचंदराम, भाखरजी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

कई भारतीय शहरों के लिए गंभीर खतरा बना समुद्र का बढ़ता जलस्तर

जलवायु में आते बदलावों के चलते जिस तरह समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है वो भारत के कई बड़े शहरों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में इस आपदा से बचने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस बारे में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर के चलते सदी के अंत तक चेन्नई और कोलकाता विशेष रूप से खतरे में हैं।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उन एशियाई महानगरों की पहचान की है जो सदी के अंत तक बढ़ते जलस्तर और उससे पैदा हुए जोखिमों का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। पता चला है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहता है तो चेन्नई, कोलकाता, यंगून, बैंकॉक, मनीला और हो ची मिन्ह सिटी बढ़ते जलस्तर की चपेट में आ सकते हैं। जानकारी मिली है कि यह एशियाई मेगासिटीज के साथ-साथ पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वीपों और पश्चिमी हिंद महासागर को भी प्रभावित कर सकती है। यह अध्ययन फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएनआरएस), फ्रांस में ला रोशेल विश्वविद्यालय और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (एनसीएआर) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुए हैं। यह अध्ययन एनसीएआर के कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल के साथ किए गए सिमुलेशन के एक सेट पर आधारित है। इसका मानना है कि इस सदी के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ेगा। वैज्ञानिक लंबे समय से इस बारे में जानते हैं कि समुद्र के बढ़ते तापमान के साथ इसके जलस्तर में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पानी गर्म होने के साथ फैलता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवों और पहाड़ों पर जमा बर्फ के पिघलने से महासागरों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी पहुंच रहा है। रिसर्च ने यह भी संकेत दिया है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि क्षेत्रीय रूप से भिन्न होगी क्योंकि समुद्र की धाराओं में बदलाव से उत्तरपूर्वी अमेरिका सहित कुछ अन्य समुद्री तटों पर जलस्तर के बढ़ने की कहीं ज्यादा आशंका है।

क्या बढ़ते तापमान के चलते समुद्र में समा जाएंगे कई शहर- आंतरिक जलवायु परिवर्तनशीलता कुछ स्थानों पर समुद्र के स्तर में 20 से 30 फीसदी तक की वृद्धि कर सकती है। इसकी वजह से भीषण तटीय बाढ़ की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए मनीला में सदी के अंत तक 2006 की तुलना में तटीय बाढ़ की घटनाएं 18 गुणा बढ़ सकती हैं। जिनके लिए सीधे तौर पर जलवायु में आते बदलाव जिम्मेवार हैं। वहीं सबसे बदतर स्थिति में जलवायु परिवर्तन और आंतरिक जलवायु परिवर्तनशीलता के चलते यह घटनाएं 96 गुणा अधिक बार हो सकती हैं। रिसर्च में सामने आया है कि सिर्फ एशिया ही नहीं आंतरिक जलवायु परिवर्तनशीलता अमेरिका के पश्चिमी तटों के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी समुद्र के स्तर में वृद्धि कर सकती है। हालांकि रिसर्च में इस बात को भी माना है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जटिल और अप्रत्याशित प्रभावों के चलते समुद्र के स्तर में वृद्धि के अनुमान काफी अनिश्चितताओं से भरे हैं। हालांकि इसके बावजूद इन बढ़ते खतरों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस बारे में एनसीएआर और अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिक ऐक्स्यू हू का कहना है कि, आंतरिक जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर या तो समुद्र के स्तर में वृद्धि को बहुत मजबूत या फिर कमजोर बना सकती है। उनके अनुसार सबसे खराब स्थिति में, जलवायु परिवर्तन और आंतरिक जलवायु परिवर्तनशीलता मिलकर केवल जलवायु परिवर्तन की तुलना में स्थानीय तौर पर समुद्र के स्तर में होती वृद्धि को 50 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह तटों के किनारे बसे बड़े शहरों पर भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा, जिसका खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

जलवायु अनुकूलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भारत जैसे देशों में छोटी दूरी के लिए होने वाला प्रवास

न्यूयार्क। प्रवास को लेकर आम धारणा यह रही है कि ज्यादातर मामलों में लोग इसके लिए एक देश से दूसरे देश या फिर लम्बी यात्रा करते हैं। हालांकि यह सच नहीं है, दुनिया में ज्यादातर प्रवास छोटी दूरी के होते हैं। इस बारे में एक नए अध्ययन से पता चला है कि छोटे दूरी के लिए किए यह प्रवास जलवायु अनुकूलन के दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखते हैं। देखा जाए तो अधिकांश लोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी कारकों जैसे जलवायु परिवर्तन आदि से बचने के लिए प्रवास के दौरान कम दूरी तय करते हैं।

यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल इकोलॉजी एंड सोसाइटी में प्रकाशित हुए हैं। यह अध्ययन भारत और अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर आधारित है। इसमें शोधकर्तओं ने भारत, घाना, केन्या और नामीबिया के शुष्क क्षेत्रों से लोगों के पलायन के कारणों और परिणामों का अध्ययन किया था। साथ ही इसे समझने के लिए 2016 और 2017 में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का साक्षात्कार लिया था।

देखा जाए तो यह शुष्क क्षेत्र दुनिया के करीब 45 फीसदी हिस्से को कवर करते हैं, जहां दुनिया की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी बसती है। यदि शुष्क क्षेत्रों की विशेषता को देखें तो यहां पानी की उपलब्धता बहुत कम और उतार चढ़ाव से भरी होती है। साथ ही यहां तापमान भी अधिक होता है। यह क्षेत्र कई तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें मिट्टी में घटती नमी, और क्षरण की बढ़ती दर शामिल हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र अनियोजित विकास, जनसंख्या में होती तीव्र वृद्धि, गरीबी, संचार साधनों की कमी के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जीविका पर बढ़ता दबाव जैसे खतरे प्रमुख हैं। यह सब ऐसे खतरे हैं जिन्होंने वहां से लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया है।

इस बारे में रिसर्च का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता डॉक्टर मार्क टेबॉथ का कहना है कि सबसे ज्यादा ध्यान अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रवास पर दिया जा रहा है। मत है कि जलवायु परिवर्तन के चलते लोगों को बड़ी संख्या में सीमाओं के पार पलायन करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता में अधिकांश लोग अवसरों का लाभ उठाने या जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव और तनाव का सामना करने के लिए अपने देश में ही बहुत कम दूरी तय करते हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उत्तरी कर्नाटक के कोलार जिले को भी शामिल किया था। जहां काम के लिए श्रमिकों और लोगों का बैंगलोर में रोजाना आना जाना आम है। इसी तरह गुलबर्गा जिले में जहां ज्यादातर लोगों की जीविका का साधन कृषि है वहां से भी लम्बे समय से बड़े शहरों की ओर पलायन हुआ है।

बढ़ते तापमान के साथ और बढ़ जाएंगी समस्याएं- देखा जाए तो यह क्षेत्र पहले ही दबाव में है ऊपर से जलवायु में आते बदलावों के चलते उनकी समस्याएं कहीं ज्यादा विकराल रूप ले लेंगी। उदाहरण के लिए यदि पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो वहां तापमान वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नतीजन उस क्षेत्र को पहले से कहीं ज्यादा चरम घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

इससे उस क्षेत्र में गर्म दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही गर्मी का कहर और तूफान का खतरा भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह के बदलाव पश्चिम, दक्षिणी अफ्रीका और भारत के शुष्क क्षेत्रों में भी सामने आ सकते हैं। यह दर्शाता है कि आने वाले दशकों में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो जाएगी।

इसी तरह केन्या के इसिओलो में जहां पशुपालन, खेती और पर्यटन आम है। उस क्षेत्र में पानी एक दुर्लभ संसाधन है। वहीं आशंका है कि भविष्य में उस क्षेत्र में जल संकट कहीं ज्यादा विकराल रूप ले लेगा।

डॉक्टर टेबॉथ का कहना है कि इन क्षेत्रों से रोजमर्रा होने वाला यह प्रवास बहुत मायने रखता है। वास्तविकता में यह लोगों के लिए जीवन और जीविका का हिस्सा बन चुका है। उनके अनुसार इस तरह का प्रवास लोगों को उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और तनावों को हल करने में मदद करता है।

इनमें जलवायु में आते बदलाव और उनसे उपजी परेशानियां भी शामिल हैं। ऐसे में उनका कहना है कि इस प्रवास के समर्थन और मदद से लोगों को अपने जीवन में दबावों से निपटने और उनका सामना करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण प्रेमियों ने बंजर भूमि पर बना दिया गार्डन, पेड़ों को एक लाइन में लगाया

बीकानेर. कहते हैं सच्ची लगन और दिलों में कुछ कर गुजरने के जज्बात हो तों व्यक्ति बंजर जमीन में भी फल उगा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया शहर के कुछ पर्यावरण प्रेमीयो ने. इन लोगों ने नत्थूसर गेट के बाहर भैरू कुटिया के पास गोचर की खाली पड़ी उबड़ खाबड़ जमीन पर जनसहयोग से मिलकर श्रमदान करके जमीन को समतल करके पेड़-पौधे लगा दिए. अब यह पेड़ बड़े आकार लेने लगे है, जिससे यहां तेज धूप में पूरी तरह छाव बनी रहती है. दोपहर में लोग इन पेड़ों की छाव में लोग बैठे रहते है.

यहां गर्मी के शुरू होते ही लोग पेड़ो और पौधो में पानी डलवाने के लिए टैंकर मंगवा रहे है और टैंकर से पानी डलवा रहे है. वही कई लोगो ने मिलकर यहां पेड़-पौधो में पानी के लिए ड्रिप सिस्टम की तकनीक अपनाई है. यहां एक स्विच ऑन करने पर एक साथ सैकड़ों पौधो में पानी शुरू हो जाता है. यहा जन सहयोग से सैकड़ों पेड़ लगाए गए है. दूर से देखने पर इस एरिया का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है. संजय सोनी ने बताया कि यहां धनसुख ओझा ने इसकी शुरुआत की जो आज भी चल रही है, पीपल के करीब 200 से अधिक, नीम के 100 से अधिक, बड़, टाली, बिल पत्र सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए है. इनमें कई पौधे तो बड़े आकार ले चुके है.

मप्र में हो रहा जल एवं पर्यावरण संरक्षण

जून तक प्रदेश में होना हैं 5,372 सरोवरों का निर्माण

भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल अमृत सरोवर ने प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। आजादी के 75वें वर्ष में लक्ष्य तो एक जिले में 75 सरोवर बनाने का था, लेकिन प्रदेश में इसकी उपयोगिता को देखते हुए पांच हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत सरोवर बनाने में मध्यप्रदेश, देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में अबतक 2,657 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और इस साल के जून माह तक टारगेट के अनुसार सभी 5,372 सरोवरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। यह सरोवर जल संरक्षण का काम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती भी होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का प्लान राज्यों को दिया था। माध्यम 75 का आंकड़ा इसलिए तय किया था कि देश आजादी का अमृत पर्व मना रहा है। देश में पानी बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में वर्ष 2022-23 में टारगेट से अधिक 5,372 अमृत सरोवर बनाने का काम हाथ में लिया गया। सबसे ज्यादा सरोवरों का निर्माण ग्राम पंचायतों में किया गया है।अमृत सरोवर बनाने के पीछे बड़ा उद्देश्य है कि तालाबों में सिंघाड़ा की खेती के साथ मत्स्य पालन भी हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मध्य प्रदेश में बनाए गए अमृत सरोवर की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मंडला जिले में कान्हा-किसली ग्राम पंचायत के मोचा में बनाए गए अमृत सरोवर का उल्लेख करते हुए कहा था कि इससे जल और पर्यावरण संरक्षण होगा और वन्यजीव भी अपनी प्यास बुझाएंगे

ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत- आजादी के अमृत महोत्सव काल में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवर जल संग्रहण के उद्देश्य के साथ-साथ स्थल विशेष से जुड़ी गौरव गाथाओं, इतिहास, विरासत, स्थानीय महान विभूतियों, धरोहरों, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, वैचारिक, संस्कृति व क्षेत्र की अन्य विशेषताओं को चिर स्थाई बनाने के लिए भी निर्मित किए जा रहे हैं। यह सरोवर पर्यावरण, जैव विविधता तथा पर्यटन के व्यापक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी उपयोगी रहेंगे। इन जल संग्रहण के कार्यों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। यह सरोवर आजादी के अमृत महोत्सव की स्मृति के साथ-साथ प्रदेश की समृद्धि एवं विकास के लिए शुरू किए गए एक नए अध्याय के रूप में भी जाने जाएंगे।

5372 अमृत सरोवर के निर्माण कार्य प्रगति पर- प्रदेश में 5372 अमृत सरोवर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, जिनमें से 2657 पूर्ण हो गए हैं। अमृत सरोवर निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में योजना में केवल नवीन कार्य ही लिए गए और अंतर्विभागीय समन्वय पर भी जोर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ जल-संसाधन, वन, मत्स्य विकास सहित नेशनल हाइ-वे अथारिटी एवं रेलवे जैसे संस्थान सहयोगी बने हैं। वित्तीय स्त्रोत के रूप में मनरेगा, वॉटर शेड विकास, 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राशि का उपयोग किया गया। जन-सहभागिता से कार्य आसान हुए हैं। अमृत सरोवर निर्माण में जो जिले आगे हैं, उनमें छिंदवाड़ा, मुरैना, बैतूल, मंदसौर और बुरहानपुर शामिल हैं। सरोवर निर्माण में 4 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि, 5 हजार से अधिक पंचायत स्तरीय अधिकारी और सवा 2 हजार उपयोगकर्ता समूह सहभागी बने हैं। विकास आयुक्त मलय श्रीवास्तव का कहना है कि वर्ष 2022-23 में 5,372 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट हाथ में लिया गया। इनमें 2,657 पूरे हो चुके हैं। हम निर्माण करने में देश में दूसरे स्थान पर हैं। शेष बचे सरोवरों का निर्माण इस साल जून माह तक पूरा कर लेंगे। वर्ष 2023-24 में नए अमृत सरोवर बनाने का प्लान नहीं है।

क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं अमृत सरोवर- जहां एक तरफ अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वहीं कई जिलों में सरोवर क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। बैतूल के चिचोली ब्लॉक के आलमपुर में 44 लाख रुपये की लागत से बनाया गया अमृत सरोवर पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और फूट गया। यहां के रिटेनिंग वॉल का 10 से 15 फीट हिस्सा फूटा था। हालांकि सबसे अधिक सरोवर बनाने के मामले में बैतूल जिला प्रदेश में टॉप-5 में शामिल है। सिवनी जिले के घंसौर की ग्राम पंचायत पहाड़ी के निचली गांव में तेज वर्षा के कारण अमृत सरोवर योजना के तहत बना अधूरा तालाब फूट गया था। डिंडोरी जिले में बना अमृत सरोवर पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के ग्राम नागझिरी में पंचायत द्वारा द्वारा बनाया गया अमृत सरोवर फूट गया जिससे कुछ किसानों की फसल प्रभावित हुई। दमोह जिले के हटा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत दमोतीपुरा के ग्राम सूरजपुरा में बनाए गए अमृत सरोवर के क्षतिग्रस्त

होने की सूचना मिली थी। इसका कारण मूसलाधार बारिश का होना बताया गया।

43 हजार तालाबों का होगा जीर्णोद्धार- प्रदेश सरकार के पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के अंतर्गत 43 हजार से अधिक जीर्ण-शीर्ण तालाबों का भी जीर्णोद्धार होगा। इस संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर लगभग 1100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रारंभ में 37,651 ताबालों का चयन किया गया था, लेकिन इसमें वर्तमान में केवल 27 हजार 710 तालाबों का ही जीर्णोद्धार किया जा सका है। शेष 9,941 जीर्ण-शीर्ण तालाबों का जीर्णोद्धार अब तक अधूरा है। 37,651 तालाबों से 28 हजार 933 तालाबों का चयन सिंचाई कार्य के लिए किया है। 6,439 तालाबों में मत्स्य पालन और दो हजार 164 तालाबों में सिंघाड़ा उत्पादन किया जाएगा।

शहीदों को समर्पित हैं सरोवर- अमृत सरोवरों पर 3 हजार 955 फ्लैग पोस्ट बनी हैं। जहां स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का कार्य भी हुआ है। यही नहीं सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के नाम 63 अमृत सरोवर समर्पित किए गए हैं। इसी तरह ऐतिहासिक महत्व के 116 स्थान के निकट सरोवर बनाए गए हैं। प्रदेश में धार्मिक महत्व के 231 स्थान के निकट और जैव विविधता-संरक्षण की दृष्टि से 342 अमृत सरोवर निर्मित हुए हैं। बहुउद्देशीय आर्थिक लाभ के लिए भी सरोवर चिन्हित किए गए हैं। मत्स्य उत्पादन में 2409, सिंघाड़ा उत्पादन में 1505 और पर्यटन के उद्देश्य से 199 सरोवर का उपयोग किया जा रहा है।

ओजोन प्रदूषण से बढ़ रहा है हृदय रोग, लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ी

एक तीन साल के अध्ययन में पाया गया कि ओजोन प्रदूषण हृदय रोग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, ओजोन गठन के पक्ष में वायुमंडलीय परिस्थितियों का निर्माण करके, दुनिया के कई हिस्सों में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाता रहेगा। अध्ययन के परिणामों से पता चलता हैं कि वृद्ध लोग विशेष रूप से ओजोन के हृदय पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के सबसे अधिक खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आबादी की तेजी से उम्र बढ़ने से भविष्य में हृदय रोग के और भी अधिक खतरे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन चीन के शीआन जियाओतोंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाओवेई वू की अगुवाई में किया गया है। ओजोन एक गैस है और फोटोकैमिकल स्मॉग या धुंध में मुख्य वायु प्रदूषक है। ओजोन प्रदूषण ओजोन परत से अलग है, जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन प्रदूषण तब बनता है जब अन्य प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। ये अन्य प्रदूषक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं जो मोटर वाहनों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और बायोमास और जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्सर्जित होते हैं। पिछले अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि ओजोन प्रदूषण हृदय और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हृदय रोग के खतरे पर इसके प्रभाव के बारे में सीमित जानकारी हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008